कार्यनीतिक निदेश:

संवृद्धि और संवहनीयता हेतु भविष्य के लिए नेविगेटिंग

जीआरआई

201, 203, 302, 305, 404, 418, 419

वैश्विक कार्यनिष्पादन और रुझान

अक्टूबर 2023 में प्रकाशित मैकिन्से की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक बैंकों ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन किया है, जो एक दशक से अधिक समय में इक्विटी पर अपना उच्चतम प्रतिलाभ (आरओई) प्राप्त कर रहा है, 2022 में 12% और 2023 में 13% की संभावना है. यह कार्यनिष्पादन, 13 साल के औसत आरओई 9.1% से काफी ऊपर है, इसके साथ ही लागत दक्षता और राजस्व वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. लागत-आय अनुपात में सात प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है, जो अधिक दक्षता की दिशा में सफल प्रयासों को दर्शाता है. वित्तीय मध्यस्थता राजस्व में भी उछाल आया है, जो 2022 में $6.8 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, इस क्षेत्र ने लगभग $400 ट्रिलियन की परिसंपत्तियों में मध्यस्थता की है - जो समग्र आर्थिक विस्तार से आगे बढ़ने का संकेत

"

वैश्विक बैंकों ने एक दशक से अधिक समय में इक्विटी पर अपना उच्चतम प्रतिफल हासिल किया है, जो 2023 में 13% तक पहुँच गया है, जिसमें भारत सहित इंडो-क्रिसेंट क्षेत्र अब दुनिया के शीर्ष कार्यनिष्पादन करने वाले वित्तीय संस्थानों में से 51% की मेजबानी कर रहा है.

है. बैंकिंग राजस्व वृद्धि विशेष रूप से भारत सहित हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्रों में मजबूत रही है, यह "इंडो-क्रिसेंट" क्षेत्र अब दुनिया के शीर्ष कार्यनिष्पादन करने वाले वित्तीय संस्थानों में से 51% की मेज़बानी करता है. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, अन्य क्षेत्रीय बाजारों के साथ, उच्च जीडीपी और जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ अभिनव व्यवधानों और कुशल सेवा वितरण मॉडल से लाभान्वित होता है. इस रिपोर्ट में बैंकों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने, उभरते जोखिमों के अनुकूल होने और ब्याज दरों में हाल की वृद्धि को नेविगेट करने की कार्यनीतिक आवश्यकता को रेखांकित किया है. इन कारकों ने शुद्ध ब्याज मार्जिन और लाभप्रदता को बढ़ाया है, तथापि कम पूंजी कारोबार मॉडल और नियामक दबावों के साथ चुनौतियां बनी हुई हैं. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र और यूबीआई के कार्यनिष्पादन के विस्तृत विश्लेषण के साथ इन वैश्विक अंतर्दृष्टि को एकीकृत करके, यह अध्याय बैंकिंग उद्योग की वर्तमान स्थिति और भविष्य के पथ का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है.यह समृद्ध परिप्रेक्ष्य हितधारकों को इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कारकों को समझने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे अधिक सूचित कार्यनीतिक निर्णय लेने में मदद मिलेगी.

बैंकिंग उद्योग संरचना

भारत में बैंकों का वर्गीकरण

अनुसूचित बैंक:भारत के बैंकों में वाणिज्यिक और सहकारी बैंक शामिल हैं. ये बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं.

- **वाणिज्यिक बैंक:**भारत में वाणिज्यिक बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों और लघु वित्त बैंकों में वर्गीकृत किया जाता है. ये बैंक विभिन्न बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न हैं, जिसमें जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना और व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना शामिल है.
  - **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी):** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसी प्रमुख संस्थाओं सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इन बैंकों का अधिकांश स्वामित्व सरकार के पास है और ये वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.
  - **निजी क्षेत्र के बैंक:** निजी क्षेत्र के बैंक सार्वजनिक और विदेशी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, तथा विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करते हैं. ये बैंक मुख्य रूप से निजी संस्थाओं के स्वामित्व-वाले होते हैं, जो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दक्षता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं.
  - **विदेशी बैंक:** विदेशी बैंक भारत में शाखाओं या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, जो बैंकिंग क्षेत्र की विविधता में योगदान करते हैं. वे भारतीय बाजार में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और उन्नत बैंकिंग तकनीकों को लाते हैं.
  - **लघु वित्त बैंक:** लघु वित्त बैंकों की स्थापना समाज के वंचित वर्गों की सेवा करने, बचत साधन उपलब्ध कराने तथा लघु व्यवसाय इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए की जाती है.
- **सहकारी बैंक:** सहकारी बैंकों को शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में विभाजित किया गया है. ये बैंक सहकारी सिद्धांतों पर काम करते हैं, मुख्य रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं.
- **शहरी सहकारी:** शहरी सहकारी बैंक शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं, जो छोटे व्यवसायों, व्यापारियों और व्यक्तियों को ऋण सुविधाएँ प्रदान करते हैं. वे स्थानीय समुदायों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
- **ग्रामीण सहकारी:** ग्रामीण सहकारी बैंक कृषि क्षेत्र और ग्रामीण समुदायों की सेवा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वे किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों

को आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ और ऋण सहायता प्रदान करते हैं, जिससे ग्रामीण विकास और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: एक अवलोकन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इसकी पहुँच काफ़ी बढ़ गई. बैंक के इतिहास में इस महत्वपूर्ण क्षण ने इसे व्यापक आबादी तक सेवाएँ पहुँचाने और वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहलों का समर्थन करने में सक्षम बनाया. यूबीआई के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर 2020 में विलय था, जहाँ आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया था. इस विलय ने यूबीआई की परिचालन क्षमताओं, ग्राहकों तक पहुँच और वित्तीय ताकत को बढ़ाया है, जिससे यह देश के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क में से एक बन गया है.

> यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में व्यापक नेटवर्क वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त उपस्थिति है, जो वित्तीय समावेशन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. बैंक का व्यापक नेटवर्क यह सुनिश्चित करता है कि बैंकिंग सेवाएँ वंचित समुदायों तक पहुँच सकें, जिससे इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में मदद मिलती है.

यूबीआई अपने ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का एक व्यापक सेट प्रदान करता है. इनमें बचत खाते, विभिन्न प्रकार के ऋण, बीमा उत्पाद और निवेश सेवाएँ शामिल हैं. बैंक लगातार नए-नए तरीके अपनाता है, ताकि अपने ग्राहकों की बदलती माँगों को पूरा करने के लिए अनुकूलित समाधान प्रदान किए जा सकें.

भारतीय बैंकिंग संरचना में यूबीआई की भूमिका

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) भारतीय बैंकिंग संरचना में, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के बीच एक प्रमुख इकाई के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. पीएसबी के रूप में, यूबीआई का अधिकांश स्वामित्व भारत सरकार के पास है. यह सरकारी नीतियों और वित्तीय समावेशन पहलों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. बैंक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम करता है, जो वंचित समुदायों सहित व्यापक आबादी के वर्ग को आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है.

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यूबीआई की मजबूत उपस्थिति शहरी और ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है. बैंक ने कृषि वित्तपोषण, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) और जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का समर्थन किया है.

यूबीआई भारत में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह कई सरकारी कार्यक्रमों में सहभागिता करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), जिसका उद्देश्य हर घर को बैंकिंग सेवाओं और एक बुनियादी बचत खाते तक पहुँच प्रदान करना है. यूबीआई ग्रामीण आबादी को बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल बैंकिंग के बारे में शिक्षित करने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी प्रदान करता है.

पीएसबी के रूप में, यूबीआई व्यक्तिगत बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और ट्रेजरी संचालन सहित विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करता है. यह विविधीकरण व्यक्तियों से लेकर बड़े निगमों तक के अपने ग्राहक आधार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है.

कार्यनीतिक पहल और प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना

यूबीआई ने अपनी सेवा सुपुर्दगी और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है. बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और अन्य डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश किया है, जिससे बैंकिंग अपने ग्राहकों के लिए अधिक सुलभ हो गई है. यूबीआई ने अपनी पहुंच का विस्तार करने और अपनी सेवा पेशकशों को बेहतर बनाने के लिए कार्यनीतिक गठबंधन और साझेदारी बनाई है. ये गठबंधन यूबीआई को उभरते बैंकिंग परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए नई तकनीकों और अभिनव समाधानों का लाभ उठाने में मदद करते हैं.

आर्थिक विकास में योगदान

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को समर्थन देकर भारत के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं. बैंक विशेष वित्तीय उत्पाद प्रदान करता है, जिसमें कार्यशील पूंजी ऋण, सावधि ऋण और अनुकूलित समाधान शामिल हैं जो एसएमई की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देते हैं.

कृषि क्षेत्र में, यूबीआई किसानों को ऋण और ऋण सुविधाएं प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ये वित्तीय सेवाएँ किसानों को उपकरण, बीज और उर्वरक खरीदने और उनकी मौसमी नकदी प्रवाह आवश्यकताओं का प्रबंधन करने में मदद करती हैं. बैंक कृषि आधारित उद्योगों का भी समर्थन करता है और वित्तीय समावेशन और शिक्षा के माध्यम से संवहनीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है.

यूबीआई व्यक्तिगत वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वैयक्तिक वित्त उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है. इनमें बचत खाते, साथ ही व्यक्तिगत, गृह और शैक्षिक ऋण शामिल हैं. सुलभ और किफायती वित्तीय समाधान प्रदान करके, यूबीआई व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे उन समुदायों की जिनकी बैंक सेवा करता है, समग्र आर्थिक भलाई में योगदान मिलता है.

यूबीआई संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के लिए भी प्रतिबद्ध है. बैंक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है और पर्यावरणीय संवहनीयता को बढ़ावा देते हुए हरित पहलों का समर्थन करता है. इसके अतिरिक्त, यूबीआई की सीएसआर गतिविधियों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना शामिल है, जो वंचितों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्पित एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है.

हरित फाइनेंस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से, यूबीआई सक्रिय रूप से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और संवहनीय प्रथाओं को वित्तपोषित करता है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और भारत को एक संवहनीय अर्थव्यवस्था में बदलने में सहायता मिलती है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एसएमई, कृषि और वैयक्तिक वित्त का समर्थन करके भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. संवहनीयता और हरित वित्तपोषण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि विकास से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल सकें.

वैश्विक बैंकिंग गति

वित्तीय वर्ष 2023-24 में वैश्विक बैंकिंग उद्योग ने उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन और पर्याप्त चुनौतियों के साथ महत्वपूर्ण बदलावों का अनुभव किया है. मैकिन्से की वैश्विक बैंकिंग वार्षिक समीक्षा 2023 के अनुसार, पिछले 18 महीने बैंकों के इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) के लिए एक दशक से भी ज्यादा समय में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं. वर्ष 2022 में आरओई बढ़कर 12% हो गया और 2023 में 13% तक पहुँचने की संभावना है, जो 13 साल के औसत 9.1% से काफी अधिक है. यह सुधार 2022 की दूसरी तिमाही के बाद से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरों में 500-आधार-बिंदु वृद्धि से प्रेरित था, जिसने शुद्ध ब्याज मार्जिन और क्षेत्र के मुनाफे को लगभग $280 बिलियन तक बढ़ा दिया.

बैंकिंग परिदृश्य को आकार देने वाले प्रमुख रुझान

1. **ऋण वृद्धि और परिसंपत्ति गुणवत्ता:** वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र ने प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत ऋण वृद्धि दिखाई है, साथ ही परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है. यह सकारात्मक प्रवृत्ति ऋण जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कम करने हेतु क्षेत्र की मजबूत क्षमता को दर्शाती है.

2. **जमा वृद्धि और नीति दर संचरण:** नीतिगत रेपो दरों में मई, 22 से फरवरी, 23 तक उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, बैंकिंग उद्योग ने जमा वृद्धि को मजबूत बनाए रखा है. यह लचीलापन बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ताओं के भरोसे और विश्वास को रेखांकित करता है, जो बैंकों के ब्याज दर जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन को उजागर करता है.

3. **वैश्विक वित्तीय परिवर्तनों के बीच आघात-सहनीयता:** बैंकिंग क्षेत्र ने वैश्विक वित्तीय चुनौतियों के बीच उल्लेखनीय आघात-सहनीयता दर्शाई है, पर्याप्त पूंजी बफर बनाए रखा है और गैर-निष्पादित ऋणों (एनपीएल) के मध्यम स्तर को बनाए रखा है. यह लचीलापन वित्तीय संवहनीयता सुनिश्चित करने और हितधारकों का विश्वास जगाने में महत्वपूर्ण रहा है.

4. **तकनीकी व्यवधान और नवाचार:** तकनीकी प्रगति, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल बैंकिंग में, बैंकिंग परिदृश्य को बदलना जारी रखा है. बैंक उत्पादकता, ग्राहक सेवा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए एआई का लाभ उठा रहे हैं. उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने से सेवा वितरण में महत्वपूर्ण लागत बचत और नवाचार को बढ़ावा मिलने की संभावना है.

5. **तुलनपत्र और संव्यवहार में बदलाव:** पारंपरिक बैंकों से गैर-पारंपरिक, कम पूंजी वाले संस्थानों जैसे कि फिनटेक कंपनियों और निजी पूंजी फर्मों की ओर परिसंपत्तियों और ग्राहकों का उल्लेखनीय बदलाव हुआ है. यह बदलाव बैंकिंग के मुख्य स्तंभों- तुलनपत्र, संव्यवहार और वितरण को नया आकार दे रहा है- जो वित्तीय सेवाओं को वितरित और प्रबंधित करने के तरीके में एक मौलिक बदलाव को दर्शाता है.

6. **मैक्रोइकॉनोमिक आउटलुक और ब्याज दरें:** मैक्रोइकॉनोमिक माहौल असमान बना हुआ है, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों में विकास और मुद्रास्फीति की संभावनाएं अलग-अलग हैं. केंद्रीय बैंकों ने उच्च मुद्रास्फीति के जवाब में ब्याज दरों में ते. जी से वृद्धि की है, जिसका बैंकिंग क्षेत्र की इक्विटी की लागत और समग्र आर्थिक संवहनीयता पर गहरा प्रभाव पड़ा है. इससे जो परिदृश्य सामने आता है, वह बैंकिंग क्षेत्र के भविष्य के कार्यनिष्पादन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा.

कार्यनीतिक निदेश:

> वैश्विक वित्तीय चुनौतियों के बावजूद, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने आघात-सहनीयता तथा सुदृढ़ ऋण एवं जमा वृद्धि का कार्यनिष्पादन किया, जो मजबूत आस्ति गुणवत्ता एवं प्रभावी जोखिम प्रबंधन को दर्शाता है.

वित्तीय वर्ष 2024 वैश्विक बैंकिंग उद्योग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों और चुनौतियों दोनों का दौर रहा है. जटिल मैक्रोइकॉनोमिक और तकनीकी बदलावों से निपटने के दौरान इस क्षेत्र को बेहतर लाभप्रदता और मजबूत ऋण वृद्धि से लाभ हुआ है. वैश्विक बैंकिंग वार्षिक समीक्षा 2023 से प्राप्त अंतर्दृष्टि वित्तीय गतिशीलता के विकास के सामने उद्योग की लचीलापन और अनुकूलनशीलता को उजागर करती है. ये रुझान बैंकों के लिए तकनीकी नवाचारों का लाभ उठाने, जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और भविष्य में विकास और संवहनीयता को बनाए रखने के लिए बदलती आर्थिक स्थितियों के अनुकूल होने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं.

भारतीय बैंकिंग उद्योग की गति

वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के प्रमुख क्षेत्रों में ऋण और जमा में मजबूत वृद्धि देखी गई. इस अवधि में परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जो ऋण जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित बैंकिंग क्षेत्र को दर्शाता है. बढ़ी हुई ऋण उपलब्धता ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का समर्थन किया, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया और समग्र आर्थिक संवहनीयता में योगदान दिया. वैश्विक वित्तीय चुनौतियों के बीच, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने मौद्रिक नीति समायोजन के लचीलेपन और प्रभावी संचरण का प्रदर्शन किया. इस गति ने न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया बल्कि भारत में वित्तीय प्रणाली की संवहनीयता और विश्वास को भी सुनिश्चित किया.

जमा वृद्धि और नीति दर संचरण

मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए मौद्रिक नीति को सुदृढ़ करते हुए मई, 2022से फरवरी, 2023 तक नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि की गई.वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, जमा वृद्धि12.9% रही,जो कि जमा दरों में 250 आधार अंकों की वृद्धि के कुशल संचरण के कारण 9.6% की नाममात्र जीडीपी वृद्धि से कहीं अधिक थी,क्योंकि बैंकों को बढ़ती ऋण मांग को वित्तपोषित करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ा है. बढ़ती ब्याज दरों के बावजूद बैंकों की जमा को आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता इस क्षेत्र की मजबूती और ब्याज दर जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन को रेखांकित करती है.

वैश्विक वित्तीय परिवर्तनों के बीच आघात-सहनीयता

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2024 में वैश्विक वित्तीय चुनौतियों के बीच उल्लेखनीय लचीलेपन को प्रदर्शित किया. वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण आर्थिक अनिश्चितताएं और वित्तीय अस्थिरता इस अवधि की विशेषता रही. भारतीय बैंक पर्याप्त पूंजी बफर बनाए रखने में कामयाब रहे, जिससे वित्तीय संवहनीयता सुनिश्चित हुई और हितधारकों में विश्वास पैदा हुआ. इसके अलावा, इस क्षेत्र ने मध्यम गैर-निष्पादित ऋण (एनपीएल) को बनाए रखा, जो प्रभावी ऋण जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और एक मजबूत नियामक वातावरण का संकेत देता है.

नीतिगत रेपो दर समायोजन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा और विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप लाने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रही है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान की गई 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी ने मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने और वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में योगदान दियाहै. मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के जवाब में 2022-23 में औसतन 6.7% से 2023-24 में 5.4% तक हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति में भी यही बात परिलक्षित होती है.

मुद्रा बाजार और रेपो दर संचरण पर प्रभाव

नीतिगत रेपो दर में समायोजन का मुद्रा बाजार दरों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा, जो प्रभावी मौद्रिक नीति संचरण को दर्शाता है. मुद्रा बाजार दरें रेपो दर में परिवर्तनों के साथ निकटता से जुड़ी हुई थीं, जो व्यापक वित्तीय प्रणाली पर आरबीआई के प्रभाव को दर्शाती हैं. इस संरेखण ने बैंक ऋण और जमा दरों में प्रभावी संचरण की सुविधा प्रदान की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि नीतिगत उपायों का अर्थव्यवस्था पर इच्छित प्रभाव पड़ा. रेपो दर परिवर्तनों के प्रति मुद्रा बाजार दरों की प्रतिक्रियाशीलता भारत में मौद्रिक नीति ढांचे की दक्षता को उजागर करती है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष 2024 का कार्यनिष्पादन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) ने पूरे वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर ऋण और जमा वृद्धि का अनुभव किया, जो इसकी मजबूत बाजार स्थिति और प्रभावी प्रबंधन को रेखांकित करता है. इस अवधि में परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता मेट्रिक में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो बैंक की जोखिम प्रबंधन और प्रतिलाभ उत्पन्न करने की बढ़ी हुई क्षमता को दर्शाता है.

ऋण एवं जमा वृद्धि

यूबीआई ने स्थिर ऋण और जमा वृद्धि का अनुभव किया, 31 मार्च, 2024 तक सकल अग्रिम 11.73% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ ₹9,04,884 करोड़ हो गया और कुल जमा 9.29% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ ₹12,21,528 करोड़ हो गया. यह वृद्धि खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विस्तार से प्रेरित थी, जिसमें सामूहिक रूप से 13.82% की वृद्धि देखी गई.

परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता

परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता में सुधार महत्वपूर्ण थे. बैंक का सकल एनपीए अनुपात 31 मार्च, 2024 तक 277 आधार अंकों की गिरावट के साथ 4.76% हो गया, जबकि शुद्ध एनपीए अनुपात 67 आधार अंकों की गिरावट के साथ 1.03% हो गया. यह यूबीआई की क्रेडिट जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की बढ़ी हुई क्षमता को दर्शाता है. वित्तीय वर्ष 2024 के लिए शुद्ध लाभ ₹13,648 करोड़ रहा, यह पिछले वित्तीय वर्ष के ₹8,433 करोड़ से काफी अधिक है, जो 61.84% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि को दर्शाता है.

इन कार्यनिष्पादन मेट्रिक्स के अधिक व्यापक विश्लेषण के लिए, इस रिपोर्ट में निर्मित और वित्तीय पूंजी पर अध्याय देखें.

बैंकिंग क्षेत्र में चुनौतियाँ और जोखिम

चुनौतियों और जोखिमों से निपटने के लिए यूबीआई का दृष्टिकोण एक अनुकूल और सुरक्षित बैंकिंग वातावरण बनाए रखने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. साइबर सुरक्षा, परिचालन जोखिम प्रबंधन, विनियामक अनुपालन, परिसंपत्ति गुणवत्ता सुधार और स्थिरता में बैंक की कार्यनीतिक पहल हितधारकों के हितों की रक्षा और दीर्घकालिक आर्थिक संवहनीयता का समर्थन करने के लिए इसके समर्पण को रेखांकित करती है.

डिजिटल व्यवधान और साइबर सुरक्षा जोखिम

डिजिटल लेनदेन पर बढ़ती निर्भरता ने बैंकों की साइबर खतरों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) ने इस जोखिम को स्वीकार किया है और अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं. इन जोखिमों को कम करने के लिए, यूबीआई ने व्यापक साइबर सुरक्षा उपाय स्थापित किए हैं. हैदराबाद में बैंक का साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई) अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा तकनीकों को लागू करने और कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर ध्यान केंद्रित करता है. यह केंद्र संभावित साइबर खतरों की पहचान करने और इससे पहले कि वे महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकें उनका समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

इसके अलावा, यूबीआई अपने सिस्टम में कमज़ोरियों की पहचान करने और उन्हें सुधारने के लिए नियमित रूप से भेद्यता आकलन और पैठ परीक्षण करता है. ये आकलन यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि बैंक की सुरक्षा अद्यतित है और परिष्कृत साइबर हमलों को विफल कर सकती है. अपने साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल को लगातार अपडेट करके और उन्नत सुरक्षा तकनीकों में निवेश करके, यूबीआई अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है.

परिचालन जोखिम

प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उन्नत तकनीकों को लागू करना ज़रूरी है, लेकिन इससे नए परिचालन जोखिम भी सामने आए हैं. इन जोखिमों में संभावित सिस्टम विफलताएँ, डेटा उल्लंघन और बैंक परिचालन में अन्य व्यवधान शामिल हैं. यूबीआई ने जोखिम प्रबंधन के लिए आईएसओ 31000 और सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए आईएसओ 27001 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ अपनी नीतियों को सुसंगत बनाकर इन समस्याओं का निवारण किया है. इसके अतिरिक्त, बैंक संभावित खतरों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए नियमित रूप से भेद्यता आकलन और पैठ परीक्षण करता है.

प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उन्नत तकनीकों को लागू करना ज़रूरी है, लेकिन इससे यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (यूबीआई) में नए परिचालन जोखिम सामने आए हैं. इन जोखिमों में संभावित सिस्टम विफलताएँ, डेटा उल्लंघन और अन्य व्यवधान शामिल हैं जो बैंक के परिचालन को प्रभावित कर सकते हैं. ये प्रयास परिचालन लचीलापन बढ़ाने और उभरते साइबर खतरों के विरुद्ध बैंक के परिचालन की सुरक्षा करने की व्यापक कार्यनीति का हिस्सा हैं. सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन और साइबर सुरक्षा प्रथाओं को अपनाकर, यूबीआई का लक्ष्य अपने ग्राहकों की सुरक्षा करना और अपनी सेवाओं में विश्वास बनाए रखना है.

विनियामक अनुपालन चुनौतियाँ

सख्त नियमों के कारण बैंकिंग क्षेत्र में मजबूत अनुपालन ढांचे की आवश्यकता होती है. यूबीआई ने आरबीआई साइबर सुरक्षा ढांचे, डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण और आईटी गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों सहित विभिन्न विनियामक ढाँचों के अनुपालन को सुनिश्चित किया है. बैंक ने कारोबार निरंतरता प्रबंधन के लिए आईएसओ 22301 और भुगतान कार्ड सुरक्षा के लिए पीसीआई-डीएसएस जैसे प्रमाणन भी हासिल किए हैं, जो उच्च विनियामक अनुपालन मानकों को बनाए रखने में मदद करते हैं.

कार्यनीतिक निदेश:

परिसंपत्ति गुणवत्ता और ऋण जोखिम

उच्च कॉर्पोरेट और कृषि ऋण स्तरों के कारण गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के साथ जुड़े मुद्दे यूबीआई के लिए लगातार एक महत्वपूर्ण चुनौती बने हुए हैं. बैंक ने मजबूत ऋण जोखिम मूल्यांकन तंत्र को अपनाकर और जिम्मेदार ऋण प्रथाओं का पालन करके परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया है. वित्तीय वर्ष 2024 में, यूबीआई ने नियंत्रण अंतर की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए नियमित डेटा डंप विश्लेषण के लिए एक प्रणाली लागू की, जिससे इसके डेटा की सटीकता और पूर्णता में वृद्धि हुई.वित्तीय वर्ष 2024 में, यूबीआई ने परिसंपत्ति गुणवत्ता सुधार में पर्याप्त प्रगति की. सकल एनपीए अनुपात घटकर 4.76% हो गया, और शुद्ध एनपीए अनुपात घटकर 1.03% हो गया. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 92.69% तक सुधर गया, जो एक मजबूत वित्तीय स्थिति बनाए रखने और ऋण जोखिमों को कम करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

संवहनीयता संबंधी विषय

बैंकों पर अपने ऋण पोर्टफोलियो को पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं के साथ जोड़ने का दबाव बढ़ रहा है. यूबीआई ने संवहनीयता के महत्व को पहचाना है और पर्यावरण संरक्षण पहलों का समर्थन करने के लिए कदम उठाए हैं. बैंक ने हरित प्रौद्योगिकियों और पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढांचे को अपनाया है, जिससे ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिला है और इसके कार्बन फूटप्रिंट कम हुए हैं. ये प्रयास पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने और एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में बैंक की प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करते हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने संवहनीयता के महत्व को पहचाना है और पर्यावरण संरक्षण पहलों का समर्थन करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाए हैं. बैंक ने अपनी ईएसजी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र ईएसजी सेल की स्थापना की है, जो संवहनीयता पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है. यूबीआई ने क्रिसिल द्वारा मान्य एक स्थायी वित्तपोषण ढांचा विकसित किया है जो हरित डिपॉजिट, हरित बॉण्ड और संवहनीयता से जुड़े ऋण जैसे उत्पादों को कवर करता है. इसके अतिरिक्त, यूबीआई ने हरित प्रौद्योगिकियों और पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे को अपनाया है, जिससे ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिलता है और इसके कार्बन फूटप्रिंट कम होते हैं. ये प्रयास न केवल पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने में मदद करते हैं बल्कि एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में बैंक की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाते हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए दिशा–निर्देश

तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति और बाजार की बदलती गतिशीलता के दौर में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) ने प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए अपनी कार्यनीतियों को लगातार अनुकूलित किया है. इन परिवर्तनों पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पहचानते हुए, यूबीआई ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने, जोखिमों का प्रबंधन करने और संवहनीयता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यनीतिक पहलों को लागू किया है. ये प्रयास बैंक की वृद्धि और दक्षता के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसके ग्राहकों और हितधारकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल परिवर्तन और एआई तथा मशीन लर्निंग को परिचालन में एकीकृत करने पर कार्यनीतिक जोर देना अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने और परिचालन लागत को कम करने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. साइबर सुरक्षा, सख्त विनियामक अनुपालन और उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के प्रति बैंक का सक्रिय दृष्टिकोण मजबूत सुरक्षा और परिचालन अखंडता सुनिश्चित करता है. तुलनपत्र प्रबंधन को अनुकूलित करके, संव्यवहार कारोबारों का मूल्यांकन करके और वितरण चैनलों को बढ़ाकर, यूबीआई का लक्ष्य बदलती ग्राहक प्राथमिकताओं को पूरा करना और लाभप्रदता में सुधार करना है. इसके अलावा, सुदृढ़ बैंकिंग प्रथाओं और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में इसका निवेश पर्यावरणीय संवहनीयता और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. ये कार्यनीतिक दिशाएँ आधुनिक बैंकिंग जटिलताओं को मार्गनिर्देशित करने, विकास को गति देने, अनुपालन सुनिश्चित करने और संवहनीयता को बढ़ावा देने के लिए यूबीआई के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं.

कार्यनीतिक दिशा	कार्रवाई	भविष्य	जीआरआई संरेखण एवं यूएनएसडीजी संदर्भ
डिजिटल परिवर्तन को अपनाया जाना	**विवरण:** कार्यकुशलता और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए परिचालन को डिजिटल बनाना और एआई-संचालित समाधान अपनाना. **कार्रवाई:** 40 से अधिक डिजिटलीकरण परियोजनाओं की शुरुआत की, 27 को पूरा किया, 13 अन्य को उन्नत किया गया. डिजिटल ऋण यात्रा को लागू किया, 400 से अधिक सुविधाओं के साथ मोबाइल बैंकिंग ऐप को "व्योम" में रिब्रांड किया, ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग को एकीकृत किया.	जनरेटिव एआई के उपयोग के मामलों का अन्वेषण करें और संचालन की निगरानी, सुधार और अनुकूलन के लिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (आरपीए सीओई) बनाया जाए.	**जीआरआई** 203:अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव **यूएनएसडीजी**

कार्यनीतिक दिशा	कार्रवाई	भविष्य	जीआरआई संरेखण एवं यूएनएसडीजी संदर्भ
साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाना	**विवरण:** एआई-संबंधित खतरों का मुकाबला करने के लिए आईटी प्रणालियों को सशक्त करना. **कार्रवाई:** हैदराबाद में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई) की स्थापना की गई. अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों को लागू किया गया. नियमित रूप से भेद्यता आकलन और पैठ परीक्षण आयोजित किए गए हैं.	उभरते साइबर खतरों से आगे रहने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाकर और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ाकर साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जाए.	**जीआरआई 418:** ग्राहक गोपनीयता **यूएनएसडीजी:**
विनियामक अनुपालन को मजबूत करना	**विवरण:** दंड से बचने के लिए कड़े नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना. **कार्रवाई:** अंतर्राष्ट्रीय मानकों (आईएसओ 31000, आईएसओ 27001) के साथ नीतियों का सामंजस्य कारोबार निरंतरता प्रबंधन के लिए आईएसओ 22301 और भुगतान कार्ड सुरक्षा के लिए पीसीआई-डीएसएस जैसे प्रमाणन प्राप्त किए गए हैं.	उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने और जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विनियामक अनुपालन ढांचे को मजबूत करना जारी रखा जाए.	**जीआरआई 419:** सामाजिक-आर्थिक अनुपालन **यूएनएसडीजी:**
ऋण और परिचालन जोखिम प्रबंधन	विवरण:ऋण मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार. कार्रवाई:ऋण मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार, नियंत्रण अंतर की पहचान करने के लिए नियमित डेटा डंप विश्लेषण, और दूरस्थ ऑडिट मॉड्यूल लागू किया गया है.	दूरस्थ लेखापरीक्षा क्षमताओं का विस्तार करना तथा लेखापरीक्षा गुणवत्ता और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए उन्नत डेटा प्रबंधन प्रणालियों को एकीकृत करना.	**जीआरआई 201:** आर्थिक कार्यनिष्पादन **यूएनएसडीजी:**
अनुकूलनीय तुलनपत्र	**विवरण:** संसाधन आबंटन में सुधार करने और लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए तुलनपत्र कार्यनीतियों को अपनाना. **कार्रवाई:** तुलनपत्र कार्यनीतियों को अनुकूलित किया, उन्नत डेटा एनालिटिक्स और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को लागू किया, और एक डिजिटल व्यापार मंच विकसित किया गया है.	उच्च-मूल्य वाले खंडों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सेवाओं को अलग-अलग करके तुलनपत्र कार्यनीतियों को परिष्कृत करना. बेहतर विश्लेषणात्मक और रिपोर्टिंग क्षमताओं के लिए डेटा लेक परियोजना का लाभ उठाना.	**जीआरआई 201:** आर्थिक कार्यनिष्पादन **यूएनएसडीजी:**
वितरण चैनलों का स्तर ऊपर उठाना	**विवरण:** हाइब्रिड और डिजिटल सेवा पेशकशों के लिए ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए वितरण चैनलों को बढ़ाना. **कार्रवाई:** डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू), व्हाट्सएप बैंकिंग (यूवीकॉन) और गूगल बिजनेस मैसेजेस (जीबीएम) के साथ वितरण चैनलों को उन्नत किया गया.	व्यक्तिगत और सुविधाजनक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे में निवेश. बहुभाषी एआई-संचालित वॉयस और संवादात्मक आईवीआर, पूर्वानुमानित आईवीआर, चैटबॉट और वॉयस बायोमेट्रिक्स के साथ डिजिटल संपर्क केंद्र क्षमताओं को बढ़ाना.	**जीआरआई 203:** अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव **यूएनएसडीजी:**
संव्यवहार कारोबारों का विस्तार करना या उनसे बाहर निकलना	**विवरण:** संव्यवहार व्यवसायों का मूल्यांकन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए तैयार किया गया है अथवा यदि वे गैर-प्रमुख हैं तो उनसे बाहर निकला जा सके. **कार्रवाई:** लेनदेन कारोबार का मूल्यांकन किया गया, स्वचालित भुगतान प्रसंस्करण के लिए यूनी पे प्लस पोर्टल को क्रियान्वित किया गया.	ऐसे लेनदेन व्यवसायों का मूल्यांकन और विस्तार जारी रखें जो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं, साथ ही गैर-प्रमुख क्षेत्रों से बाहर निकलने की संभावना भी रखते हैं.	**जीआरआई 203:** अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव **यूएनएसडीजी:**
संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना	**विवरण:** संवहनीय परिचालन और जलवायु-अनुकूल वित्तपोषण के लिए प्रतिबद्धता. **कार्रवाई:** क्रिसिल द्वारा प्रमाणित एक संवहनीय वित्तपोषण ढांचा विकसित किया गया, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को समर्थन दिया गया, छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए, जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा दिया गया.	नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाएं, वैश्विक मानकों के अनुरूप स्थिरता रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण प्रथाओं को बढ़ाना.	**जीआरआई 302:** ऊर्जा, जीआरआई **यूएनएसडीजी:**